दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, मंगलवार 28 दिसंबर 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-04, अंक- 91

महत्वपूर्ण एवं खास

अजीत डोभाल की टीम में शामिल हुए विक्रम मिसरी, सरकार ने बनाया डिप्टी एनएसए

नई दिल्ली (आरएनएस)। चीन के मुद्दे के एक्सपर्ट और बीजिंग में पूर्व भारतीय राजदूत विक्रम मिसरी को आज राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवायल में डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया गया है। 1989 बैच के आईएफएस अधिकारी मिश्री, पंकज सरन की स्थान लेंगे। पंकज सरन 31 दिसंबर 2021 को ऑफिस छोड़ देंगे। इससे पहले सरन रूस में भारत के राजदूत थे। प्रदीप कुमार रावत को चीन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किए जाने के बाद विक्रम मिसरी एनएससीएस में शामिल कर लिया गया है। विक्रम मिसरी पूर्व में प्रधानमंत्री कार्यालय में काम कर चुके हैं और इंडो पैसिफिक में रणनीतिक माहौल से अच्छी तरह से परिचित है। डिप्टी एनएसए नियुक्त किए जाने के बाद वो अभ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा दो और भी डिप्टी एनएसए हैं, जिसमें एक राजेंद्र खन्ना है और दूसरे दत्ता पंडसलगीर हैं।

उत्तराखंड में ओमीक्रॉन के आए 3 केस यमन नागरिक भी मिला पॉजिटिव

देहरादून (आरएनएस)। उत्तराखंड में ओमीक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यमन नागरिक समेत तीन लोगों में और ओमीक्रॉन की पुष्टि हुई है। डीजी हेल्थ डा. तृप्ति बहुगुणा की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। बताया कि रुड़की में कोरोना संक्रमित मिले यमन नागरिक में ओमिक्रोन वैरियंट की पुष्टि हुई है। इसके अलावा दिल्ली में ओमिक्रोन संक्रमित परिजनों से मिलकर दून लौटे राजपुर रोड निवासी बुजुर्ग दंपती भी ओमिक्रोन संक्रमित मिले। इससे पहले स्कॉटलैंड से लौटी दून के बसंत विहार निवासी युवती में ओमिक्रोन की पुष्टि हुई थी। राज्य में अब तक ओमिक्रोन के चार मामले आ चुके हैं। बसंत विहार निवासी युवती के माता-पिता कोरोना संक्रमित है। उनकी जीनोम सिक्वेंसिंग की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उधर, दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डा. आशुतोष सयाना का कहना है रिपोर्ट प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग को भेज दी गई है। कॉलेज में हर माह एक हजार जांच का लक्ष्य रखा गया है।

उत्तराखंड में लगा नाइट कर्फ्यू ..

देहरादून (आरएनएस)। उत्तराखण्ड के देहरादून में कोरोना के नए वेरिएंट 'ओमिक्रॉन' और कोविड केसों में बढ़ोतरी के बीच सरकार ने उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। जिला प्रशासन और पुलिस को सख्त हिदायत दी गई है कि नाइट कर्फ्यू को प्रभारी ढंग से लागू किया जाए। इसे लेकर मुख्य सचिव डॉ. संधु की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में नाईट कर्फ्यू रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। कोविड-19 के घोषित किया है जो कि तेजी से फैलने की क्षमता रखता है। इस सन्दर्भ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 को दिशा-निर्देश जारी किए गए है।

मध्यप्रदेश में 1 जनवरी से ट्रेनों में होगा बड़ा बदलाव

भोपाल (आरएनएस)। मध्यप्रदेश में नव वर्ष एक जनवरी 2022 से रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। भारतीय रेलवे एक जनवरी 2021 से 20 जनरल डिब्बों पर अनारक्षित टिकट के जरिए यात्रा करने का मौका दे रहा है यानि नए साल 2022 में आप अब अनारक्षित टिकट पर सफर कर सकेंगे। यात्री नए साल पर लखनऊ इंटरसिटी और कृषक एक्सप्रेस समेत 10 जोड़ी ट्रेनों में जनरल टिकट के जरिए सफर कर सकेंगे।इसके अलावा रेलवे ने दो ट्रेनों में सेकंड और थर्ड क्लास एसी डिब्बों में स्थाई बढ़ोतरी का ऐलान किया है और पांच अन्य ट्रेनों में अस्थाई रूप से डिब्बों की भी संख्या बढ़ाई जाएगी। वही जबलपुर रेल मंडल से होकर गुजरने वाली रानी कमला पति स्टेशन से अगरतला के बीच चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल यात्री गाड़ी नंबर 01665 एवं 01666 आगामी 6 जनवरी एवं 9 जनवरी 2022 को रद्द रहेगी। इसी तरह इटारसी से जबलपुर होकर प्रयागराज छौकी के बीच चलने वाली पैसेंजर गाड़ी नंबर 11117 भी आगामी एक जनवरी से 10 जनवरी के बीच कटनी तक चलेगी। वापसी में भी यह पैसेंजर गाड़ी नंबर 11118 प्रयागराज छौकी से चलकर सतना होकर इटारसी की जगह कटनी स्टेशन पर ही समाप्त हो जाएगी।

कोरोना संक्रमण के साथ ओमिक्रोन का खतरा बढ़ा 24 घंटे में 6531 नए मामले, 387 मरीजों की मौत

» ओमीक्रोन के मामले भी बढ़कर 578 पहुंचे

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में 24 घंटे में कोरोना के 6531 केस आए। जबकि ओमीक्रोन के मामलों की संख्या भी बढ़कर 578 पहुंच गई है। इन बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्यप्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा की तर्ज पर दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू लागू किया जा रहा है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में लगातार बढ़ रहे ओमिक्रॉन के खतरे के बीच राहत की खबर ये है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6531 नए मामले सामने आए। जबकि 7141 लोग ठीक होकर घर लौटे। इस तरह देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 3 करोड़ 42 लाख 37 हजार 495 हो गई है। रिकवरी रेट 98.40 प्रतिशत है। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 75,841 है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस से नए संक्रमित पाए जाने के बाद इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,47,93,333 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या गिरकर 75,841 हो गई है। इस दौरान 315 और मरीजों की मौत होने से मृतक संख्या बढ़कर 4,79,997 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सक्रिय मामलों की संख्या एक प्रतिशत से गिरकर 0.22 प्रतिशत पर सिमट गई है। रिकवरी रेट पिछले साल मार्च महीने के बाद सबसे उच्चतम है। पिछले 84 दिनों में दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2 प्रतिशत से कम होकर 0.87 प्रतिशत हो गया है। पिछले 43 दिनों में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट एक प्रतिशत से कम होकर 0.63 प्रतिशत हो गया है।

ओमिक्रोन के 156 नए मामले- भारत में ओमिक्रॉन वैरिएंट के एक दिन में सर्वाधिक 156 मामले सामने आए हैं। इसी के साथ देश में कोरोना वायरस के इस नए स्वरूप से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 578 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को आंकड़ों में बताया कि ओमिक्रॉन से संक्रमित 578 लोगों में से 151 ठीक हो गए हैं या विदेश चले गए हैं। ओमीक्रोन के संक्रमण के ये मामले 19 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सामने आए हैं। दिल्ली में सर्वाधिक 142, इसके बाद महाराष्ट्र में 141, केरल में 57, गुजरात में 49, राजस्थान में 43 और तेलंगाना में 41 मामले सामने आए हैं।

कोरोना जांच व टीकाकरण में तेजी- केंद्र सरकार के अनुसार अभी तक 67.29 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 141.70 करोड़ टीके की खुराक दी जा चुकी है। वहीं अब देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 75, 841 है जो पिछले साल मार्च महीने के बाद से सबसे कम है। इस देश में सक्रिय मामले एक प्रतिशत से भी कम होकर 0.22 प्रतिशत पर सिमट गई है।

पुणे की एमआईटी यूनिवर्सिटी में 13 छात्र संक्रमित- पुणे के एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार डॉ. प्रशांत दवे ने जानकारी दी कि 13 छात्रों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। सभी छात्रों को अलग-अलग क्वारंटाइन किया गया है। सैंपल जीनोम अनुक्रमण के लिए भेज दिए गए हैं। साथ ही छात्रों की ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी जुटाई जा रही है।

बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने में केरल सबसे आगे, छत्तीसगढ़ दसवें पायदान पर

» नीति आयोग की रिपोर्ट में किया गया खुलासा

नई दिल्ली (आरएनएस)। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के मामले में देश के दक्षिणी राज्य काफी आगे हैं। नीति आयोग ने हेल्थ इंडेक्स जारी किया है और इसमें पहले चारों पायदान पर केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने जगह बनाई है। नीति आयोग के चौथे स्वास्थ्य सूचकांक में देश के बड़े राज्यों में केरल टॉप पर और उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है। स्वास्थ्य क्षेत्र के सभी मानकों पर केरल शीर्ष पर रहा।

चौथा स्वास्थ्य सूचकांक वर्ष 2019-20 की अवधि के लिए है। सरकारी थिंक टैंक की ओर से तैयार की गई इस रिपोर्ट में बड़े 19 राज्यों की लिस्ट देखिए तो बिहार 18वें और उत्तर प्रदेश 19वें स्थान पर है। छोटे राज्यों में मिजोरम ने सर्वोच्च स्थान पाया है जबकि केंद्रशासित प्रदेशों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर ने सभी मानकों पर निचला स्थान प्राप्त किया।स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग और विश्व बैंक की तकनीकी मदद से यह रिपोर्ट तैयार की गई है।

दिल्ली के शैक्षणिक संस्थानों के नजदीक शराब के ठेके खुलवा रहे हैं मनीष सिसोदिया : कांग्रेस

नई दिल्ली (आरएनएस) । दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ. अनिल कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी दिल्ली की आबकारी नीति के खिलाफ शुरु से ही अपना विरोध जता रही है। प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 12ई - पटपड़गंज की आचार्य निकेतन कॉलोनी के रिहायशी क्षेत्र में खुले शराब के ठेके का पिछले चार दिनों से विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं, आर.डब्लू.ए. और मार्केट एसोसिएशन के लोगों को समर्थन देने पहुँचे। चौ. अनिल कुमार ने वहां मौजूद क्षेत्रीय निवासियों और मार्केट एसोसिएशन के लोगों को आश्वासन दिया कि हम किसी भी कीमत पर शराब का ठेका खुलने नही देंगे।चौ. अनिल कुमार ने कहा कि आचार्य निकेतन में चल रहे शैक्षिक संस्थान के नीचे शराब का ठेका खोलना पूरी तरह आबकारी नीति के नियमों का उलंघन है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के शराब मंत्री मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री भी है। यही कारण है कि मनीष सिसोदिया नियमों को ताक पर रखकर राजधानी में रिहायशी क्षेत्रों और शैक्षणिक संस्थानों के नजदीक शराब के ठेके खोल रहे है, शायद इसलिए ही दिल्ली सरकार ने युवाओं की शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 वर्ष की है। पटपड़गंज क्षेत्र में शराब की दुकान का विरोध करने वालों में प्रदेश अध्यक्ष चौ0 अनिल कुमार के साथ आर.डब्लू.ए. और मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी हरी सिंह, जितेन्द्र, पी.के. वर्मा, सुधीर शर्मा, राजवीर गोला, राजेश यादव और विनय दूबे मुख्य रुप से मौजूद थे।

हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार आज होगा कैबिनेट विस्तार

चंडीगढ़ (आरएनएस)। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार का कैबिनेट विस्तार होने वाला है। मंगलवार को शाम 4 बजे नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह किया जाना है। माना जा रहा है कि असंतुष्ट वर्गों को साधने के लिए यह फैसला लिया गया है। हरियाणा सीएमओ की ओर से कैबिनेट विस्तार के बारे में जानकारी दी गई है। फिलहाल यह पता नहीं चला है कि किन मंत्रियों खट्टर कैबिनेट में शामिल किया जाना है। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार का यह दूसरा कैबिनेट विस्तार है। इससे पहले इसी साल 14 नवंबर को भी कैबिनेट का विस्तार हुआ था। कैबिनेट विस्तार में जिन नेताओं के नाम चर्चा में हैं, उनमें से एक देवेंद्र सिंह बाली का है। वह जननायक जनता पार्टी के टोहाना सीट से विधायक हैं। इसके अलावा एक भाजपा नेता को भी कैबिनेट में हिस्सेदारी दी जा सकती है। भाजपा की ओर से जिन नामों की चर्चा है, उनमें विधानसभा के स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता शामिल हैं। वह पंचकूला सीट से विधायक हैं। इसके अलावा हिसार के विधायक डॉ. कमल गुप्ता का भी नाम चल रहा है।

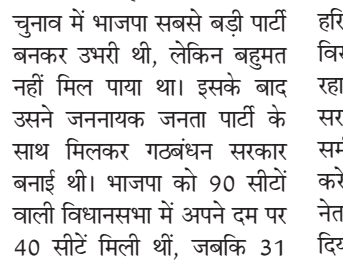

2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बहुमत नहीं मिल पाया था। इसके बाद उसने जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई थी। भाजपा को 90 सीटों वाली विधानसभा में अपने दम पर 40 सीटें मिली थीं, जबकि 31 सीटों के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर पर रह गई थी। 10 सीटें जननायक जनता पार्टी को मिली थीं। इस तरह भाजपा और जेजेपी की मिलाकर विधानसभा में कुल 50 सीटें हैं।

किसान आंदोलन के बाद हरियाणा सरकार में यह कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। माना जा रहा है कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार इसके जरिए सामाजिक समीकरणों को साधने का प्रयास करेगी और जाट समुदाय के नेताओं को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।

भाजपा के गढ़ रहे चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत

नई दिल्ली (आरएनएस) । चंड़ीगढ़ नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने आज ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आम आदमी पार्टी पहली बार चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में उतरी थी और भाजपा के गढ़ रहे चंडीगढ़ नगर निगम की 14 वार्डों में जीत दर्ज की। इस ऐतिहासिक जीत पर खुशी व्यक्त करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के सभी विजयी उत्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की यह जीत पंजाब में आने वाले बदलाव का संकेत है। चंडीगढ़ के लोगों ने आज भ्रष्ट राजनीति को नकारते हुए 'आप' की ईमानदार राजनीति को चुना है। वहीं, दिल्ली के डिप्टी सीएम एवं 'आप' के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह जीत संकेत है कि अगर विकल्प हो, तो लोग 'ईमानदारी और काम करने वाली राजनीति' को मौका देना चाहते हैं। वहीं, आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर पर भी एक विकल्प बन कर उभरी है। दूसरी तरफ, सोशल मीडिया पर चर्चा है कि चंडीगढ़ के बाद दिल्ली एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी का परचम लहराएगा। 'आप' के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि चंडीगढ़ नगर निगम से चली जीत की यह लहर दिल्ली नगर निगम तक पहुंचेगी।भारतीय जनता पार्टी के गढ़ रहे चंडीगढ़ नगर निगम के कुल 35 वार्डों में बीते 24 दिसंबर को मतदान हुआ था। वर्तमान में चंडीगढ़ नगर निगम में भाजपा की ही सरकार थी। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी पहली बार मैदान में उतरी थी। आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने के लिए दिन-रात मेहनत की। गत 19 दिसंबर को 'आप' संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में एक जनसभा को संबोधित कर वहां की जनता से आम आदमी पार्टी की ईमानदार राजनीति को एक मौका देने का आह्वान किए थे। चंडीगढ़ की जनता ने 'आप' संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनकी ईमानदार राजनीति पर मुहर लगाने का निर्णय लिया और चंड़ीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को 14 वार्डों में ऐतिहासिक जीत दिला दी। भाजपा के भ्रष्टचार से परेशान जनता ने उसके मेयर तक को हरा दिया। चंडीगढ़ नगर निगम में इस जीत से साफ है कि इस बार पंजाब बदलाव चाहता है। अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत पर खुशी व्यक्त की है। 'आप' संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, ''चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी की यह जीत पंजाब में आने वाले बदलाव का संकेत है। चंडीगढ़ के लोगों ने आज भ्रष्ट राजनीति को नकारते हुए 'आप' की ईमानदार राजनीति को चुना है। 'आप' के सभी विजयी उम्मीदवारों एवं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत-बहुत बधाई। इस बार पंजाब बदलाव के लिए तैयार है।वहीं, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, ''चंडीगढ़ के लोगों ने आज अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति में और उनके नेतृत्व में भरोसा जताया है। इसके लिए चंडीगढ़ के एक-एक वोटर का तहेदिल से शुक्रिया।

मसूरी में नए साल के जश्न पर लगी पाबंदियां हटी

देहरादून (आरएनएस)। उत्तराखण्ड के देहरादून में ओमीक्रोन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में क्रिसमस और थर्टी फर्स्ट की रात होने वाली पार्टियों में भीड़ पर नियंत्रण के लिए जारी आदेश जिला प्रशासन ने वापस ले लिया। अब सामान्य आयोजन की तरह लोग बुलाए जा सकेंगे। वहीं रात दस बजे तक आयोजन करने की समय की पाबंदी भी हट गई है।

ओमीक्रोन के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिले की गाइड लाइन जारी होते ही अगले दिन शासन से गाइड लाइन जारी की। 25 दिसंबर को जारी राज्य सरकार की गाइड लाइन से पहले भीड़ या त्योहारों पर नियंत्रण के लिए कोई गाइडलाइन नहीं थी। ऐसे में डीएम ने 24 दिसंबर की रात जिले के लिए गाइड लाइन जारी की थी। जिसमें बढ़ते संक्रमण पर लगाम के लिए फोकस किया गया था। आदेश के तहत क्रिसमस और थर्टी फर्स्ट की रात होने वाले आयोजनों में 100 से ज्यादा लोग नहीं बुलाए जा सकते थे। वहीं पार्टी जैसे आयोजन भी रात दस बजे तक करने की छूट दी गई थी। इस गाइड लाइन के आते ही होटल, रेस्त्रा, बार और क्लब संचालक परेशान थे। अब राज्य की गाइड लाइन आने पर डीएम ने रविवार को आदेश करते हुए 24 दिसंबर को जारी आदेश को वापस ले लिया है।

नीति आयोग ने राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के चौथे संस्करण को किया जारी

नई दिल्ली (आरएनएस)। नीति आयोग ने आज 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के चौथे संस्करण को जारी किया है। इस रिपोर्ट को स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत शीर्षक दिया गया है। यह राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग उनके स्वास्थ्य परिणामों में साल-दर-साल क्रमिक प्रदर्शन के साथ-साथ उनकी व्यापक स्थिति के आधार पर तय करती है।

इस रिपोर्ट का चौथा दौर राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के 2018-19 से 2019-20 की अवधि में व्यापक प्रदर्शन और क्रमिक सुधार को मापने और उन्हें रेखांकित करने पर केंद्रित है। इस रिपोर्ट को संयुक्त रूप से नीति

आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, सीईओ अमिताभ कांत, अतिरिक्त सचिव डॉ. राकेश सरवाल और विश्व बैंक की वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ शीना छाबड़ा ने जारी किया। इस रिपोर्ट को नीति आयोग ने विश्व बैंक की तकनीकी सहायता और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के गहन परामर्श से विकसित किया है।

राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक वार्षिक साधन है। यह स्वास्थ्य से संबंधित परिणामों, शासन व सूचना और प्रमुख इनपुट/प्रक्रियाओं के क्षेत्र के तहत एक समूह में एकत्रित 24 संकेतकों पर आधारित एक भारित (वेटेज) समेकित सूचकांक है। परिणाम संकेतकों के लिए उच्च अंक के साथ हर एक क्षेत्र को इसके महत्व के आधार पर भार तय किया गया है।

समान राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच तुलना सुनिश्चित करने के लिए, रैंकिंग को बड़े राज्यों, छोटे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में बांटा गया है।

राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए एक मजबूत और स्वीकार्य क्रियाविधि का उपयोग किया जाता है। सम्मत संकेतकों पर नीति आयोग अनुरक्षित पोर्टल के जरिए आंकड़े ऑनलाइन इकट्ठे किए जाते हैं। इसके बाद एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के जरिए चयनित एक स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी के माध्यम से इन आंकड़ों की पुष्टि कराई जाती है। सत्यापन के लिए प्रमाणित डेटा शीट को राज्यों के साथ साझा भी किया जाता है। इसके बाद किसी भी असहमति या विवाद को सुलझाने के लिए राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की जाती है। इस प्रकार तैयार की गई अंतिम शीट को राज्यों के साथ साझा किया जाता है और सहमत होने के बाद आंकड़ों को अंतिम रूप दिया जाता है। इनका उपयोग विश्लेषण और रिपोर्ट-लेखन के लिए किया जाता है।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने कहा, 'राज्यों ने राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जैसे सूचकांकों को अपने संज्ञान में लेना शुरू कर दिया है और उनका नीति निर्धारण व संसाधन आवंटन में उपयोग किया है। यह रिपोर्ट प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद, दोनों का एक उदाहरण है।

वहीं, सीईओ अमिताभ कांत ने कहा, इस सूचकांक के जरिए हमारा उद्देश्य न केवल राज्यों के ऐतिहासिक प्रदर्शन, बल्कि उनके क्रमित प्रदर्शन को भी देखना है। यह सूचकांक राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और एक-दूसरे से सीखने की प्रवृति को प्रोत्साहित करती है।

इस सूचकांक को 2017 से संकलित और प्रकाशित किया जा रहा है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को मजबूत स्वास्थ्य प्रणालियों के निर्माण और स्वास्थ्य सेवा के वितरण में सुधार के लिए प्रेरित करना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रोत्साहन के लिए इस सूचकांक को जोड़ने का निर्णय लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस वार्षिक सूचकांक के महत्व पर फिर से जोर दिया है।